

आनंद बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड

बनाम

इसके कर्मचारी

7 मई, 1963

(पी.बी. गजेंद्रगढकर, के.एन.वांचू, के.सी. दास गुप्ता जेजे)

औद्योगिक विवाद - कर्मचारियों का निष्कासन - घरेलू पूछताछ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप- औद्योगिक सीमा न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), एस. 10 (1) (डी).

प्रतिवादी आनंद बाजार में रिपोर्टर के रूप में पत्रिका कार्यरत था। आनंद बाजार प्रमुख संवाददाता पत्रिका छुट्टी पर चली गई. छुट्टी पर जाने से पहले उन्होंने .नियुक्त 'एम' के दौरान अस्थायी रूप से मुख्य रिपोर्टर के रूप में कार्य करना उसकी अनुपस्थिति. प्रतिवादी इससे संतुष्ट नहीं था व्यवस्था और इसलिए उसने असाइनमेंट को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया कार्यवाहक मुख्य संवाददाता द्वारा उन्हें आवंटित किया गया। अधिनियम चीफ रिपोर्टर ने प्रबंध-निदेशक से शिकायत की कि प्रतिवादी उसे आवंटित कार्यों की अनदेखी कर रहा था उपरोक्त शिकायत के आधार पर जांच की गई प्रतिवादी के विरुद्ध आयोजित किया गया। यह दिन-प्रतिदिन आयोजित किया जाता था और प्रतिवादी ने गवाहों से विस्तार से जिरह की। जांच अधिकारी ने संपादक से पूछताछ की अनुमति नहीं दी प्रतिवादी की ओर से इस आधार पर कि वह नहीं था भौतिक गवाह. जांच अधिकारी ने पाया कि आरोप प्रतिवादी के विरुद्ध सिद्ध किया गया था। प्रबंधजांच रिपोर्ट स्वीकार कर ली और उन्हें पदमुक्त कर दिया सेवा।

उपरोक्त विवाद अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी के बीच है श्रम न्यायालय में भेजा गया।

श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि घरेलू पूछताछ थी प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं किया गया, प्रतिवादी के रूप में न्याय को जांच करने की अनुमति नहीं थी एकल गवाह. श्रम न्यायालय ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया प्रतिवादी को बहाल करें.

यह अभिनिर्धारित किया गया कि घरेलू जांच में यह सक्षम है जांच अधिकारी किसी गवाह से पूछताछ करने से इंकार कर दे यदि कोई प्रश्न ईमानदारी से निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसे अस्वीकार कर दें इनमें से कोई भी इस उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है जाँच करना।

(2) यह नहीं कहा जा सकता कि जांच अधिकारी ने कार्रवाई की है दुर्भावनापूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत के लिए संपादक की गवाह के रूप में जांच करने से इंकार कर दिया प्रतिवादी या द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को अस्वीकार करने में गवाहों के प्रति प्रतिवादी इस आधार पर कि ये थे पूछताछ के उद्देश्य से अप्रासंगिक।

(3) कि एक बार पता चल जाए कि घरेलू पूछताछ है निष्पक्ष, बिना द्वेष के और सिद्धांतों के अनुरूप प्राकृतिक न्याय और उक्त जांच के निष्कर्ष विकृत नहीं हैं तो श्रम न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष पर विचार करना, और यह जांचने के लिए कि क्या निष्कर्ष घरेलू द्वारा दर्ज किए गए हैं न्यायाधिकरण सही है या गलत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 633/1962

द्वितीय श्रम न्यायालय, पश्चिम बंगाल, केस नं. 1958 का आठवीं-सी-226 दिनांक 8 दिसंबर 1959 के पुरस्कार से विशेष अनुमति द्वारा अपील

ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री और के. बलदेव मेहता, के लिए अपीलकर्ता

एन. सी. चटर्जी, एम.के. राममूर्ति, आर.के. गर्ग, एस.सी. अग्रवाल और डी. पी. सिंह, उत्तरदाताओं की ओर से।

7 मई, 1963. न्यायालय का निर्णय गजेंद्रगढ़कर जे. सुनाया गया

यह अपील एक औद्योगिक से उत्पन्न होती है अपीलकर्ता के बीच विवाद, आनंद बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड, और उत्तरदाता, इसके कर्मचारी। अपीलकर्ता एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और का कारोबार करती है समाचार पत्रों का मुद्रण और प्रकाशन, अर्थात् 'आनंद बाजार।' पत्रिका' जो एक बंगाली दैनिक है, 'देश' जो एक बंगाली है साप्ताहिक, और 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' जो एक अंग्रेजी दैनिक है समाचार पत्र, श्री पुलकेश दे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था मार्च 1940 में अपीलकर्ता का पत्रकार के रूप में प्रबंधन, और रहा है तब से अपीलकर्ता के साथ तब तक काम करता रहा जब तक वह" नहीं था 15 मई, 1958 को अपीलकर्ता द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपीलकर्ता के कर्मचारियों के संघ ने इसे उठाया निर्वहन और इसके बारे में एक औद्योगिक विवाद उठाया। में था यूनियन द्वारा आग्रह किया गया कि डिस्चार्ज करें। श्री सरकार का सेवाएँ अवैध थीं और वह इसका हकदार था बहाली और/या मुआवजा. यह विवाद था पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्णय हेतु भेजा गया 25 सितम्बर 1958 को द्वितीय श्रम न्यायालय में श्रम न्यायालय ने 8 दिसंबर, 1959 को फैसला सुनाया अपीलकर्ता को श्री सरकार को बहाल करने और उन्हें भुगतान करने का निर्देश दिया 'उसकी मजबूर बेरोजगारी की अवधि के लिए उसकी परिलब्धियाँ। ऐसा प्रतीत होता है कि 27 जनवरी 1959 को अपीलकर्ता ने भुगतान कर दिया था श्री सरकार को कुछ धनराशि, और इसलिए, पुरस्कार उसे निर्देशित करता है के प्रावधानों के तहत श्री सरकार को परिलब्धियों का भुगतान करना पुरस्कार, राशि के संबंध में समायोजन किया

जाना चाहिए अपीलकर्ता द्वारा उसे पहले ही भुगतान कर दिया गया है। यह इसके खिलाफ है निर्णय दें कि अपीलकर्ता विशेष रूप से इस न्यायालय में आया है छुट्टी।

वर्तमान औद्योगिक विवाद के लिए जिम्मेदार तथ्य पार्टियाँ बहुत अधिक नहीं हैं और इन्हें बहुत संक्षेप में बताया जा सकता है आरंभ। ऐसा प्रतीत होता है कि 16 दिसम्बर, 1957 को श्री. शिबदास भट्टाचार्जी जो के मुख्य रिपोर्टर थे आनंद बाजार पत्रिका, अवकाश पर चले गए। आगे बढ़ने से पहले छोड़ें, श्री भट्टाचार्जी ने श्री मधुसूदन को नियुक्त किया चक्रवर्ती को उनके कार्यकाल के दौरान अस्थायी रूप से मुख्य रिपोर्टर के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया अनुपस्थिति। तदनुसार, उन्होंने इस आशय का एक पत्र लिखा और इसकी प्रतियां आनंद बाजार पत्रिका के संपादक को भेजीं। उक्त अखबार के समाचार संपादक को, प्रमुख को लेखाकार और रिपोर्टिंग विभाग को। पत्र था प्रबंध निदेशक को संबोधित। आनंद बाजार का पत्रिका, और इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर टांग दी गई आनंद बाजार पत्रिका का रिपोर्टिंग अनुभाग

श्री सरकार जो रिपोर्टरों में से एक के रूप में काम कर रहे थे, ने लिया इस व्यवस्था का अपवाद और प्रबंध का साक्षात्कार लिया निदेशक से उक्त व्यवस्था को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। प्रबंध निदेशक ने उन्हें बताया कि पत्र लिखा जा चुका है लेखा विभाग के कहने पर श्री भट्टाचार्जी द्वारा- उल्लेख करें, क्योंकि लेखा विभाग चाहता था कि यदि कोई हो अवकाश रिक्ति के दौरान व्यवस्था की गई थी, होनी भी चाहिए खातों को सक्षम करने के लिए एक दस्तावेज द्वारा प्रमाणित विभाग अब तक कार्यवाहक व्यक्ति से निपटने के लिए वित्तीय लेनदेन का संबंध था। श्री सरकार नहीं हिले साक्षात्कार से संतुष्ट होकर, उन्होंने लिखना शुरू किया प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा और इसकी एक प्रति लटका दी नोटिस बोर्ड पर पत्र. इस पत्र में उन्होंने कड़ा रुख अपनाया श्री भट्टाचार्जी द्वारा की गई व्यवस्था का अपवाद और श्रीमान ने जिस पत्र के

विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया। भट्टाचारजी ने उक्त व्यवस्था के साक्ष्य के लिए लिखा था। "मुझे कोई कारण नहीं मिला". श्री सरकार ने उस पत्र में कहा, "से उस नकली पत्र का सम्मान करो और इसलिए, मैं खड़ा रहूंगा मेरा अपना अधिकार और योग्यता है, अपना कार्य स्वयं तय करें और कार्य करें तदनुसार जब तक मुख्य रिपोर्टर अपना कार्यालय फिर से शुरू नहीं कर देता।" यह पत्र 20 दिसंबर, 1957 को लिखा गया था। इसकी प्रति श्री सरकार द्वारा समाचार संपादक को पत्र भेजा गया था संपादक और रिपोर्टिंग विभाग को।

श्री सरकार, उनके पत्र में दी गई धमकी सच है द्वारा आवंटित कार्यों की अनदेखी करते प्रतीत हुए कार्यवाहक मुख्य संवाददाता, श्री चक्रवर्ती। जब ये बात उन्होंने लिखा, प्रबंध निदेशक के संज्ञान में लाया गया 31 दिसम्बर 1957 को श्री सरकार को पत्र लिखकर आह्वान किया गया उनसे पूछा जाए कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए उनके घोर कदाचार और विध्वंसक आचरण के लिए। इसके बाद, श्री सरकार ने प्रबंध निदेशक से कहा कि वह शांत हैं वह अपना पत्र नोटिस बोर्ड से हटाने को तैयार हैं और वह उसका हिसाब दिया दिसंबर के बीच जो काम उन्होंने खुद को सौंपा था 16 से 31 दिसम्बर, 1957 तक।

इसी बीच कार्यवाहक चीफ रिपोर्टर ने इसकी शिकायत की प्रबंध निदेशक ने कहा कि श्री सरकार अनदेखी कर रहे हैं उसे आवंटित कार्य। अंत में, प्रबंध निदेशक ने 11 जनवरी 1958 को श्री सरकार को लिखा कि उनके द्वारा अपनाए गए उद्दंड रवैये को देखते हुए, प्रबंध निदेशक को कारण बताने के लिए श्री सरकार को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्यों न उसे उसकी अवज्ञा के लिए बर्खास्त कर दिया जाए? पर 12 जनवरी, 1958 को श्री सरकार ने विस्तृत व्याख्या दी उसके आचरण का. चूंकि इस स्पष्टीकरण का इलाज नहीं किया गया था प्रबंध निदेशक को संतोषजनक बताते हुए

उन्होंने श्रीमान को सूचित किया। सरकार ने 29 जनवरी, 1958 को अपने पत्र द्वारा जांच की मांग की उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उसे सामने पेश होना होगा श्री एस.के. बसु, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के संपादक, अपने कमरे में 1 फरवरी 1958 को दोपहर 1 बजे

श्रीमान. इसके बाद बसु ने पहले ही आरोपों की जांच कर ली श्री सरकार को आपूर्ति की गई। इस पूछताछ में श्री सरकार साक्ष्य देने वाले गवाहों से विस्तृत जिरह की उसके खिलाफ खुद गवाही दी. प्रमुख जो प्रश्न जांच अधिकारी को भेजा गया था क्या श्री सरकार ने दिये गये वैधानिक आदेशों का उल्लंघन किया है उसे कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर द्वारा? जांच अधिकारी साक्ष्यों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्रीमान सरकार जानबूझकर कानून की अवज्ञा करने की दोषी थी कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर के आदेश जो ठीक से थे नियुक्त. यह रिपोर्ट 14 अप्रैल, 1958 को बनाई गई थी।

अपीलकर्ता के प्रबंधन ने तब रिपोर्ट पर विचार किया, पूछताछ में मिले सबूतों की जांच की और नतीजे पर पहुंचे निष्कर्ष कि श्री सरकार घोर कदाचार के दोषी थे और बर्खास्त किये जाने योग्य थे, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लंबे समय तक अखबार प्रबंधन को अपनी सेवाएं दीं उसे सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया। तदनुसार, पर 15 मई, 1958 को प्रबंधन ने श्री सरकार को एक पत्र लिखा उनकी सेवाएं मई से समाप्त कर दी गई हैं 16, 1958. श्री सरकार को इसके बदले में एक महीने का वेतन दिया गया नोटिस, और उसे अपना बकाया जमा करने की सलाह दी गई, जिसमें शामिल है उसके द्वारा अर्जित मजदूरी, ग्रेच्युटी और उसके बदले में एक महीने का वेतन 19 मई, 1958 को दोपहर दो बजे कैश कार्यालय से नोटिस। पत्र में श्री सरकार को यह भी बताया गया कि भविष्य निधि को समाप्त करने के संबंध में

अधिकारियों को सलाह दी गई थी उनकी सेवा और वह, उचित समय पर, भविष्य निधि उन्हें देय राशि का भुगतान किया जाएगा। मोटे तौर पर कहा जाए तो ये हैं वे तथ्य जो वर्तमान विवाद को जन्म देते हैं अपीलकर्ता और संघ जिसने श्री सरकार का मामला उठाया।

क्षेत्राधिकार की सीमा जो एक श्रम न्यायालय या एक औद्योगिक न्यायाधिकरण ऐसे मामलों से निपटने का कार्य कर सकता है विवादों का अच्छी तरह निपटारा हो चुका है। यदि एक की समाप्ति औद्योगिक कर्मचारी की सेवाओं को आगे बढ़ाया गया है उचित घरेलू पूछताछ जिसके अनुसार आयोजित की गई है प्राकृतिक न्याय के नियमों और निष्कर्षों के साथ कहा गया है कि, जांच न्यायाधिकरण को विकृत नहीं कर रही है औचित्य या शुद्धता पर विचार करने का हकदार नहीं है उक्त निष्कर्षों का. यदि, दूसरे बैंड पर, मैं कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त करना' प्रबंधन के पास है दुर्भावनापूर्ण या बदले की भावना से कार्य किया गया है या किसी के द्वारा कार्य किया गया है कर्मचारी को उसके ट्रेड यूनियन के लिए दंडित करने की इच्छा गतिविधियों, न्यायाधिकरण पर्याप्त देने का हकदार होगा कर्मचारी को उसकी बहाली का आदेश देकर सुरक्षा प्रदान करना, या के भुगतान का निर्देश उनके पक्ष में दिया। मुआवजा; लेकिन अगर जांच उचित रही है और का आचरण तो फिर, कर्मचारी को बर्खास्त करना प्रबंधन का कर्तव्य नहीं है न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जांच अधिकारी, या प्रबंधन द्वारा पारित आदेश के साथ उक्त निष्कर्ष को स्वीकार करने के बाद।

वर्तमान मामले में, श्रम न्यायालय ने लिया हुआ प्रतीत होता है यह विचार कि जांच निष्पक्ष नहीं थी और के नियमों के अनुसार संचालित नहीं किया गया था प्राकृतिक न्याय। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, ट्रिब्यूनल विवाद की खूबियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा पार्टियों के बीच और उसके बाद अपने निष्कर्ष दर्ज किए

हैं संबंधित द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सराहना करना पक्ष अपने तर्कों के समर्थन में। इसने इसे धारण कर लिया है श्री सरकार का उनके पत्र को लटकाना उचित नहीं था सूचना पट्ट। लेकिन प्रबंधन ने यह विचार किया कि इस तथ्य को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी पता चलते ही श्री सरकार ने पत्र हटा दिया था प्रबंधन ने उनके आचरण पर आपत्ति जताई। श्रम न्यायालय के अनुसार, श्री भट्टाचार्जी नहीं थे श्री चक्रवर्ती को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया रिपोर्टर छुट्टी पर अपनी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान, और इसलिए, यह सोचा कि श्री चक्रवर्ती वैध पोशाक में नहीं थे श्री सरकार को श्रीमान के दौरान कार्य आवंटित करने का अधिकार। भट्टाचार्जी की अनुपस्थिति. इस प्रश्न के संबंध में कि श्री. सरकार ने अपना खुद का साइनपोस्ट, लेबर कोर्ट तय कर लिया था द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण कहानी से संतुष्ट नहीं था अपीलकर्ता के गवाह और किसी भी घटना में, यह माना गया कि श्री सरकार द्वारा इस संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण सही नहीं था अनुचित. इन निष्कर्षों पर ही आदेश दिया गया है श्रम न्यायालय द्वारा बहाली के पक्ष में फैसला सुनाया गया है श्री सरकार का.

पहला प्रश्न जो हमारे निर्णय के लिए आता है वह है कि क्या श्रम न्यायालय ने जांच को सही ठहराया श्री बसु द्वारा की गई जांच निष्पक्ष जांच नहीं थी। समर्थन में इस निष्कर्ष पर श्रम न्यायालय ने कहा कि श्री बसु श्री सरकार को एक भी गवाह से पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी थी उनकी ओर से", और कुछ बहुत ही प्रासंगिक प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया था अपीलकर्ता की जिरह में श्री सरकार द्वारा रखा गया गवाह. इसमें यह भी कहा गया है कि सजा दी गयी है श्री सरकार के लिए यह बहुत गंभीर है और उसने सोचा कि यह था अपीलकर्ता के लिए पहले संपादक से परामर्श करना आवश्यक है पर निर्णय लेना श्री सरकार को जो सजा दी जानी चाहिए। इन श्रम न्यायालय के अनुसार तथ्य, दुर्भावना को उजागर करते हैं इस मामले में अपीलकर्ता,

और इसलिए, वह इसके लिए तैयार नहीं था घरेलू जांच में आये निष्कर्षों को स्वीकार करें। श्री बसु की विफलता के बारे में पहला बिंदु लेते हुए श्री सरकार को अपने एक भी गवाह की जांच करने की अनुमति दें की ओर से, यह आश्चर्य की बात है कि श्रम न्यायालय को ऐसा करना चाहिए था एक अवलोकन किया जिससे यह आभास होता है कि श्रीमान. सरकार बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ करना चाहती थी। का जिनके एक भी गवाह से पूछताछ नहीं होने दी गई। श्रम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी भ्रामक है। यह सच है कि एक स्तर पर श्री सरकार ने कहा था कि उन्होंने ऐसा किया है गवाहों की एक सूची दायर की, लेकिन वह सूची इसमें नहीं है हमारे सामने रिकॉर्ड करें. हालाँकि, हमारे सामने रिकॉर्ड में क्या है? यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि श्री सरकार केवल जांच करना चाहते थे एक गवाह और वह है आनंद बाजार के संपादक पत्रिका। किसी भी मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उसने दबाव डाला केवल एक गवाह से पूछताछ का उनका दावा। यह गैर है- के दौरान श्री बसु द्वारा रखे गए रिकॉर्ड से अस्पष्ट रूप से साबित हुआ घरेलू पूछताछ के दौरान और दिए गए बयान से श्रम न्यायालय के समक्ष श्री सरकार स्व. "एकमात्र गवाह", श्री सरकार ने श्रम न्यायालय के समक्ष कहा। "मैंने उद्धृत किया घरेलू पूछताछ में पूछताछ की अनुमति नहीं दी गई अधिकारी." अतः इसे व्यापक बनाना अनुचित है बयान कि श्री सरकार को जांच करने की अनुमति नहीं दी गई थी एकल गवाह. सच्ची स्थिति तो यह है कि केवल एक ही गवाह है श्री सरकार द्वारा जांच किये जाने का इरादा था और श्री बसु ने किया इसकी अनुमति न दें. की कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है घरेलू पूछताछ में श्री बसु ने इस पर विचार किया संकीर्ण प्रश्न जिस पर विचार करने के लिए उन्हें बुलाया गया था संपादक सक्षम होता। कोई सामग्री न दें सहायता, और इसलिए, उन्होंने सोचा कि श्रीमान का अनुरोध। सरकार को उनसे जांच की इजाजत नहीं मिल सकी. नहीं हो सकता घरेलू पूछताछ में संदेह है कि जांच अधिकारी को जांच करने से इंकार करने का

अधिकार हैं एक गवाह यदि वह प्रामाणिक हो तो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कहा गया गवाह अप्रासंगिक या सारहीन होगा। यदि ऐसे गवाह से पूछताछ करने से इंकार करना, या दूसरे को अनुमति देने से इंकार करना प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य इच्छा का परिणाम प्रतीत होते हैं जांच अधिकारी का भाग व्यक्ति को वंचित करना उस पर अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर देने का आरोप लगाया गया निःसंदेह, यह बहुत गंभीर मामला होगा। लेकिन मैं वर्तमान मामले में, किसी को केवल लंबे रिकॉर्ड को देखना होगा इस बात से संतुष्ट होने के लिए कि जांच श्री बसु ने की थी विस्तार से पूछताछ की और श्री सरकार को पूरी छूट दी प्रबंधन के गवाहों से जिरह करना; पूछताछ थी दिन-प्रतिदिन आयोजित किया जाता है और रिकॉर्ड दिखाता है कि कैसे श्री सरकार ने विस्तृत रूप से क्रॉस के अपने अधिकार का उपयोग किया है- प्रबंधन के गवाहों से निपटने में परीक्षा. इसलिए, हम श्री सरकार के मना करने में ऐसा नहीं सोचते हैं संपादक से पूछताछ करने का अनुरोध, जांच अधिकारी हो सकता है कहा जाता है कि उसने मनमौजी या दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है। ऐसा लगता है ईमानदारी से सोचा है कि उक्त गवाह नहीं होगा सामग्री या प्रासंगिक. ऐसा होने पर हम ऐसा नहीं सोचते यह परिस्थिति जांच को अनुचित बना सकती है। श्रम न्यायालय द्वारा की गई दूसरी आलोचना कहा गया कि पूछताछ में कुछ बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न थे श्री बसु द्वारा अस्वीकृत। हमारी राय में यह आलोचना है पूरी तरह गलत धारणा. हमने की कार्यवाही को देखा है पूछताछ और हम अधिकांश प्रश्नों से संतुष्ट हैं जो अस्वीकृत थे वे उचित रूप से अस्वीकृत थे; वास्तव में श्रीमान चटर्जी यह नहीं दिखा पाए कि आलोचना कैसी हुई श्रम न्यायालय द्वारा इस भाग में दिया गया निर्णय उचित है। श्री सरकार द्वारा गवाहों से किये गये कुछ प्रश्न न केवल अप्रासंगिक थे, बल्कि पूरी तरह से अनुचित थे, और ऐसा ही था उन प्रश्नों को अस्वीकार करना श्री बसु का कर्तव्य है। अलावा, मामले के इस पहलू से निपटने में, श्रम न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

था कि प्रासंगिकता प्रश्नों का निर्णय श्री बसु को करना था जो थे पूछताछ करना; और भले ही लेबर कोर्ट ने ले लिया विचार यह है कि कुछ प्रश्न जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था प्रासंगिक, इससे जरूरी नहीं कि जांच अनुचित हो जाए या अनुचित, जब तक कि निश्चित रूप से, प्रासंगिक को अस्वीकार न किया जाए प्रश्न, यह दिखाया जा सकता है कि श्री बसु माला का अभिनय कर रहे थे फाइड. अतः यह आलोचना भी उपयोगी है। फिर, श्रम न्यायालय ने कहा कि यह उसका कर्तव्य था निर्णय लेने से पहले प्रबंधन को संपादक से परामर्श करना होगा श्री सरकार को मिलने वाली सजा पर। हम हैं आश्चर्य है कि श्रम न्यायालय को इसे ऐसे ही मानना चाहिए था जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का एक वैध कारण। हमें यह समझ नहीं आता कि यह किस प्रकार आवश्यक या अनिवार्य था प्रबंधन को कोई भी लेने से पहले संपादक से परामर्श करना होगा श्री सरकार के खिलाफ कार्रवाई. इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि हालाँकि प्रबंधन ने श्री बसु के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया ऐसा कहा गया है कि श्री सरकार घोर कदाचार के दोषी थे श्री सरकार द्वारा इसे ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता से कार्य करना अखबार के साथ उनका लंबा जुड़ाव, और इसलिए, इसके बजाय उसे बर्खास्त करते हुए, इसने उसे केवल सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आधार दिया गया है श्रम न्यायालय ने संपादक से परामर्श करने में विफलता के कारण ऐसा किया प्रबंधन का दुर्भावनापूर्ण आचरण पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेबर के समक्ष एक तर्क का आग्रह किया गया था कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी बाहरी व्यक्ति है पूछताछ शुरू से ही अमान्य थी. ये आपत्ति हो चुकी थी खत्म- श्रम न्यायालय द्वारा शासित और, हमारी राय में, श्रम द्वारा कोर्ट सही था. ऐसा भी प्रतीत होता है कि इसका आग्रह पहले भी किया गया था श्रम न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा जो श्री बसु को दिया था एक घटना के कारण श्री सरकार के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ भविष्य निधि के प्रबंधन के संबंध में स्थान आनंद बाजार पत्रिका के

कर्मचारी। यह प्रकट होता है कि श्री बसु और आनंद बाजार के प्रबंध निदेशक पत्रिका के ट्रस्टी थे 3 अन्य ट्रस्टियों के साथ उक्त निधि और का संचालन ट्रस्टी इस ट्रस्ट की काफी बड़ी राशि की अनुमति दे रहे हैं प्रबंधन द्वारा ऋण के रूप में दिए गए फंड की आलोचना की गई फंड के सदस्य, और आंदोलन के परिणामस्वरूप उस संबंध में आगे बढ़ाया गया, श्रीमान. बसु जो मूलतः थे अगले चुनाव में फंड के ट्रस्टी का चुनाव नहीं किया गया। हालाँकि, यह विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया और पक्षकारों ने 7/9 मार्च, 1957 को समझौते की शर्तों पर सहमति हुई श्री सरकार द्वारा आग्रह किया गया था कि चूँकि उन्होंने नेतृत्व कर लिया है में ट्रस्टियों के आचरण के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया भविष्य निधि से प्रबंधन को ऋण देना, श्रीमान. बसु और प्रबंध निदेशक उनके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। यहां तक की इस तर्क को श्रम न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है इस आधार पर कि श्री सरकार ने इस पर कोई विवाद नहीं उठाया था पूछताछ के समय दयालु। इसके अलावा तकनीकी हालाँकि, हम संतुष्ट हैं कि कोई सबूत नहीं है यह दिखाने के लिए कि श्री बसु या आनंद के प्रबंध निदेशक बाजार पत्रिका ने श्री सरकार के प्रति कोई दुर्भावना रखी। वास्तव में, सबूत इंगित करते हैं कि श्री सरकार आसानी से खत्म हो गए हैं- आंदोलन में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका की रेटिंग करें ऋण का कथित आक्षेपित लेनदेन। इसलिए हमारी राय में, श्रम न्यायालय ने इसे अस्वीकार करके सही किया था विवाद.

इस प्रकार स्थिति यह है कि श्रम का निष्कर्ष कोर्ट ने कहा कि जांच निष्पक्ष नहीं थी और अपीलकर्ता श्री सरकार को पदमुक्त करने में दुर्भावनापूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता निरंतर। हालाँकि हमने बार-बार इस ओर ध्यान दिलाया है औद्योगिक न्यायनिर्णयन औद्योगिक की रक्षा कर सकता है और करना भी चाहिए कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाना, दुर्भावनापूर्ण या दुर्भावनापूर्ण होने का निष्कर्ष उत्पीड़न का मामला केवल वहीं निकाला जाना चाहिए जहां सबूत मौजूद हों इसे उचित ठहराने का नेतृत्व

किया; ऐसी खोज भी नहीं की जानी चाहिए कारणात्मक ढंग से या हल्के-फुल्के ढंग से। हमारी राय में, नहीं सामग्री को वर्तमान में श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अपने निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए कार्यवाही या तो जाँच अनुचित था, या श्री सरकार को पदमुक्त करने में अपीलकर्ता का आचरण दुर्भावनापूर्ण था।

जैसे ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो निष्कर्ष यह निकलता है कि श्रम न्यायालय के पास गुणों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था पार्टियों के बीच विवाद, और पूछताछ करने के लिए कि क्या घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष सही थे या नहीं। हालाँकि, हमने श्री चटर्जी को विस्तार से सुना है सवाल यह है कि क्या श्री भट्टाचार्जी के पास अधिकार था श्री चक्रवर्ती को कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर के रूप में नियुक्त करना उनकी छुट्टी पर अनुपस्थिति के दौरान, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत हुआ यदि साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नियुक्ति श्रीमान द्वारा की गई है। भट्टाचार्जी प्रचलित नियमों के विपरीत थे संस्था या अभ्यास के साथ असंगत था, यह हो सकता है शायद उनकी शिकायत उचित हो जो श्री बसु को होनी चाहिए थी संपादक को इस धारणा पर जांच करने की अनुमति दी गई कि संपादक रीमेलिंग नियमों या अभ्यास से बात कर सकता था उस ओर से. श्री सरकार का मामला यह है कि संपादक अंदर हैं पूरे रिपोर्टिंग विभाग का प्रभार और मामले में मुख्य रिपोर्टर छुट्टी पर चला जाता है, यह संपादक पर निर्भर करता है कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर की नियुक्ति करें। यह है उल्लेखनीय है कि यद्यपि श्री सरकार ने यह मुद्दा उठाया है प्रारंभ में, उन्होंने शपथ पर इसके समर्थन में कुछ भी नहीं कहा है वह अभ्यास जिस पर वह भरोसा करता है। श्री चटर्जी के पास है अपने साक्ष्य में हमें कई बयानों का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने काफी हद तक स्वीकार किया कि श्री सरकार ने अब-यहां एक बना दिया है शपथ पर स्पष्ट बयान कि लंबी अवधि के दौरान कि वह इस पेपर के साथ काम कर रहे थे, अभ्यास हमेशा से था कि जब चीफ रिपोर्टर छुट्टी पर गए तो संपादक अवकाश रिक्ति

में एक कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर नियुक्त किया गया। ऐसा स्पष्ट करने में श्री सरकार की विफलता अपनी दलील के समर्थन में बयान या किसी घटना का उल्लेख करना महत्व से रहित नहीं है।

लेकिन इसके अलावा, पहले भी प्रचुर सबूत पेश किए गए हैं श्रम न्यायालय जो यह दर्शाता है श्री सरकार का तर्क उचित नहीं है. हम' पास होना मुझे पहले ही पता चल गया था कि श्री सरकार ने प्रबंध निदेशक को देखा है और पत्र में उन्होंने नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया था 20 दिसम्बर 1957 श्री सरकार ने स्पष्ट कहा था कि प्रबंध निदेशक ने उन्हें यही बताया था कि किस बात की प्रबंध निदेशक को पता था कि "लेखा" था विभाग का जोर प्रमुख द्वारा किसी को अधिकृत करने पर है रिपोर्टर के छुट्टी पर जाने से पहले किसके जरिए वित्तीय लेन-देन, यदि कोई हो, होगा." यह वक्तव्य स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रबंध निदेशक ने श्री सरकार को बताया कि लेखा विभाग लिखित में कुछ चाहता था चीफ रिपोर्टर जब भी छुट्टी पर जाते तो किसे दिखाते अपने कार्यकाल के दौरान कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर के रूप में कार्य करेंगे अनुपस्थिति। यह कथन श्री सरकार के पत्र में निहित है और प्रबंध निदेशक द्वारा उसे जो बताया गया था वह उसका प्रतीक है वह स्वयं। इसलिए, प्राधिकरण द्वारा किया जाना था इसके अनुसार सम्पादक द्वारा नहीं बल्कि मुख्य रिपोर्टर द्वारा कथन।

फिर हमारे पास श्री चक्रवर्ती का निदेशक को लिखा एक पत्र है विभाग 3 जनवरी 1958 को लिखा गया। यह पत्र दर्शाता है कि कई मौकों पर जब चीफ रिपोर्टर गए थे छुट्टी पर, श्री चक्रवर्ती को का काम सौंपा गया था मुख्य संवाददाता. उस क्षमता में, उन्होंने इसका प्रबंधन किया था विभाग ने अन्य रिपोर्टरों को कार्यभार आवंटित किया और एक कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। श्री ए.के. सरकार आनंद बाजार पत्रिका के प्रबंध निदेशक कौन हैं? शपथपूर्वक कहा गया कि पत्रिका में

यह सामान्य प्रथा है कि जब मुख्य रिपोर्टर या किसी भी अनुभाग के प्रमुख अनुपस्थित रहता है, वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने उत्तराधिकारी को नामांकित करता है अनुपस्थिति। पत्र को लेकर कुछ विवाद हुआ था श्री भट्टाचार्य द्वारा श्री चक्रवर्ती को नामांकित करते हुए लिखा गया एक कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर, और श्रीमान ने इसे उचित रूप से स्वीकार किया। ए.के. सरकार ने कहा कि यह पत्र लिखा गया था क्योंकि लेखा विभाग ने कुछ लिखने पर जोर दिया कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर की नियुक्ति दिखाएं। पूर्व में, मुख्य रिपोर्टर काम के लिए मौखिक व्यवस्था करता था उसकी अनुपस्थिति के दौरान. अधिनियम आईएनजी चीफ रिपोर्टर के पास अधिकार है को भुगतान करने के लिए लेखा विभाग से नकद लेना जब भी आवश्यक हो रिपोर्टर। अतः इसका प्रमाण श्री ए.के. सरकार ने अपीलकर्ता के मामले को स्थापित किया कि श्री भट्टाचार्य की नियुक्ति उचित थी। उनकी अनुपस्थिति में चक्रवर्ती को कार्यवाहक मुख्य रिपोर्टर नियुक्त किया गया। आनंद बाजार पत्रिका के दो रिपोर्टरों द्वारा दिए गए साक्ष्य श्री जी.के. घोष और श्री ए. चौधरी का प्रभाव समान है। इस प्रकार, इस तथ्य के अलावा कि श्री सरकार ने नहीं लिया है अपनी याचिका के समर्थन में शपथ, के नेतृत्व में साक्ष्य अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि श्री भट्टाचार्य ने जो कुछ किया 16 दिसम्बर, 1957 को प्रचलित के अनुसार था संस्था में अभ्यास करें.

वास्तव में, यह सामान्य ज्ञान लगता है कि यदि मुख्य रिपोर्टर छुट्टी पर जाता है, कुछ को सक्षम करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए उनकी अनुपस्थिति के दौरान अन्य रिपोर्टर को उनके स्थान पर कार्य करना होगा और के अन्य प्रमुखों को तदनुसार सूचित करना चाहिए विभागों और प्रबंध निदेशक को। यह संभव है अन्य संस्थानों के पास अन्य नियम हो सकते हैं, या वे अपना सकते हैं एक अन्य प्रकार का अभ्यास, लेकिन साक्ष्य के आधार पर, इसमें शामिल किया गया इस मामले में, श्री सरकार की दलील को बरकरार रखना असंभव है श्री भट्टाचार्य ने अपने अधिकार के

बाहर काम किया और उन्होंने इसलिए, उग्रवादी रवैया अपनाना उचित था जिसका खुलासा उनके 20 दिसंबर 1957 के पत्र से हुआ था जिसे उनके द्वारा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया। यह शायद ही है यह बताना आवश्यक है कि भले ही श्री सरकार के पास ए श्रीमान की नियुक्ति के मामले में शिकायत चक्रवर्ती, उन्हें अति नहीं अपनानी चाहिए थी को नियुक्त करने की घोषणा करके उग्रवादी रुख अपनाया स्वयं अपने कर्तव्य और श्रीमान से कोई आदेश नहीं लेंगे। चक्रवर्ती इसलिए, हम यह नहीं सोचते कि गुण-दोष के आधार पर भी श्रीमान चटर्जी का यह तर्क सही है कि श्री का इन्कार। बसु द्वारा अखबार के संपादक से पूछताछ करना अनुचित था, इसे विकृत या दुर्भावनापूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता इस तर्क को बनाए रखने के लिए कि पूछताछ में कहा गया है संपादक की जांच किये बिना अधिकारी का चयन करना अनुचित है और किया भी है प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया। निःसंदेह श्री चटर्जी ने हमारे सामने इस तथ्य का आग्रह किया कि श्री. सरकार को लंबी और सराहनीय सेवा का श्रेय प्राप्त है यह संस्था, और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने इसमें भाग लिया था राष्ट्रीय आन्दोलन और अपना कैरियर अपनाया था देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं से पत्रकारिता। वह, इसलिए, हमसे इस बात पर विचार करने की अपील की गई कि क्या अपीलकर्ता उसे अपने रोजगार में बहाल करने के लिए कहा जाना चाहिए। कब मामले का यह पहलू पेश हुए श्री शास्त्री के समक्ष रखा गया अपीलकर्ता के लिए, श्री शास्त्री ने उनसे परामर्श करने के बाद हमें बताया ग्राहक कदाचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसे अपीलकर्ता श्री सरकार के विरुद्ध प्रमाणित माना गया है उसे वापस लेने का मन नहीं था.

परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और आदेश पारित हो जाता है श्रम न्यायालय को अलग रखा गया है। जैसा कोई आदेश नहीं होगा लागत के लिए। अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।